

प्रेषक:

पी०के०पात्रो,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, फॉरेस्ट कालोनी,  
इन्दिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 22 नवम्बर, 2014

विषय: जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून-अब्दुल्लापुर 400 के०वी० डीसी (क्वाड) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 51.3958 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को 35 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 869/1जी-3860(दे०दून) दिनांक 30.09.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-8-9/2014-एफ.सी. दिनांक 08-09-2014 में निहित प्राविधानों के क्रम में श्री राज्यपाल जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून-अब्दुल्लापुर 400 के०वी० डीसी (क्वाड) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 51.3958 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को 35 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

- (1) वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (2) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दुगुनी 102.7916 हे० अवन्त (Degraded) वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
- (3) वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन की गयी उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, FRI, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (4) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- (5) प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाता है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
- (6) उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- (7) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के संक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- (8) वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये मूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (9) प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित ट्रान्समिशन लाइन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर बौने पौधों (विशेषकर औषधीय पौधे) यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
- (10) मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण हेतु बड़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
- (11) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।



- (12) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
- (13) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- (14) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- (15) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
- (16) प्रयोक्ता एजेन्सी के ध्येय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण विनियमित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
- (17) निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
- (18) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों, अन्य सामान्य शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार के आदेश संख्या F.No. 8-09/2014-FC, दिनांक 08.09.2014 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोषक के शासनादेश संख्या 198/7-जी-सी-89-3-89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-01-न्याय प्रशासन-501-सेवाएँ और सेवा फीस-01-की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही निष्पादित किया जायेगा।
- (19) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी हैंड बुक के Annexure-V में दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
- (20) प्रश्नगत वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रुपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।  
वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) = जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य x लीज अवधि

99

- (21) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(पी०के० पात्रो)  
अपर सचिव।

संख्या: 203 (1)/X-4-14/02(30)/2014, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केंद्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ०आर० आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी देहरादून।
6. उप महाप्रबन्धक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, 400/200क०वी० उपकेन्द्र, ग्राम व पो० शंरपुर शिमला वाईपास रोड देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
Akhil  
(अखिलेश मिश्रा)  
अनु सचिव।